

20



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 99]
No. 99]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2003/चैत्र 19, 1925
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2003/CHAITRA 19, 1925

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2003
अंतिम जांच परिणाम

विषय :—दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फैरो सिलिकोन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

.....

सं. 14/8/2002-डीजीएडॉ.—वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और उसकी सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन तथा वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 को ध्यान में रखते हुए;

क. प्रक्रिया:

2. निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है:

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद् पश्चात प्राधिकारी कहा गया है) को घरेलू उद्योग की ओर से मै0 इंडियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायज लि0, भुवनेश्वर से उपर्युक्त नियमों के तहत एक लिखित याचिका प्राप्त हुई है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया(जिसका एतद्पश्चात् संबद्ध देशों/क्षेत्रों के रूप में उल्लेख किया गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फैरो सिलिकोन के पाटन का आरोप लगाया गया है;

(ii) प्राधिकारी ने भारत में स्थित दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया के दूतावासों (सोफिया, बुल्गारिया में भारत के दूतावास के जरिए) को उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू होने की प्रक्रिया से पहले याचिकाकर्ता द्वारा की गई पूर्ण प्रलेखित याचिका के प्राप्त होने के बारे में अधिसूचित किया ;

(iii) प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची 1 के अध्याय शीर्ष 72 के अन्तर्गत आने वाले फैंरो सिलिकोन के आयातों के संबंध में पाटनरोधी प्रक्रिया को शुरू करते हुए दिनांक 11 अप्रैल, 2002 को भारत के राजपत्र असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना जारी करके प्रकाशित किया ।

(iv) प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया से निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी:

क) मैसिदोनिया

मै0 जुगोचोराम, 91215-जुगुनक्वस, मैसिदोनिया गणराज्य,

ख) दक्षिण अफ्रीका

मै0 समानकोन क्रोम, 6, हौलार्ड स्ट्रीट, जोहान्सबर्ग 2001

मै0 निमाग लिमिटेड, 37, लिनकोलन स्ट्रीट, बुडमीड ईस्ट, गाउटेंग,
दक्षिण अफ्रीका.

(v) दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया के दूतावासों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने के अनुरोध के साथ नियम 6(2) के अनुसार जांच को शुरू करने के बारे में सूचित किया गया था । निर्यातकों को भेजी गई पत्र की एक प्रति, अगोपनीय याचिका और प्रश्नावली भी निर्यातकों के नाम और पते के साथ उनको भेजी गई थी ।

(vi) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगने के लिए भारत में फैंरो सिलिकोन के ज्ञात आयातकों को प्रश्नावली भेजी गई थी ।

(vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 11 जुलाई, 2002 की अधिसूचना के द्वारा प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए और प्रारंभिक जांच परिणाम की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों और उद्योग एसोसिएशनों को प्रेषित की तथा उन्हें पत्र की तारीख से 40 दिन के भीतर लिखित में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया ।

(viii) प्राधिकारी ने दक्षिण अफ्रीका और मैसिडोनिया के दूतावास को प्रारंभिक जांच परिणामों की प्रति उपलब्ध करवाई और निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक जांच परिणामों पर अपने विचार प्रस्तुत करने की सलाह देने का अनुरोध किया;

(ix) क्षति के बारे में याचिकाकर्ता से अतिरिक्त सूचना मांगी गई थी, वह भी प्राप्त हो गई थी ।

(x) प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय अंश उपलब्ध कराए और इन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुला रखा । उन सभी हितबद्ध पक्षकारों, जिन्होंने लिखित में निरीक्षण के लिए अनुरोध किया था, को सार्वजनिक फाइल के निरीक्षण की अनुमति दी गई ।

(xi) प्राधिकारी ने जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सूचना को मंगाया और उसका सत्यापन किया तथा घरेलू उद्योग के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं के परिसरों की जांच की ।

(xii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की ईष्टतम उत्पादन लागत तथा माल को बनाने तथा बेचने की लागत का हिसाब लगाने के लिए सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर लागत जांच भी करवाई ।

(xiii) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 18.9.2002 को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । मौखिक रूप से विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दायर करने का अनुरोध किया गया था । पक्षकारों को विरोधी पार्टियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रतियां प्राप्त करने और उनका खंडन, यदि कोई हो, को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी ।

(xiv) उपर्युक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचार किए गए आवश्यक तथ्य/आधार का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था और इस पर प्राप्त अभिमतों पर अंतिम जांच परिणामों में उचित रूप से विचार किया गया है ।

(xv) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बेचने के लिए उत्पादन की ईष्टतम लागत निकालने के लिए लागत जांच भी की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम का पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(xvi) *** इस अधिसूचना में यह चिन्ह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और प्राधिकारी द्वारा नियमों के तहत इसे ऐसा ही माने जाने का द्योतक है।

(xvii) जांच 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसंबर 2001 तक की अवधि के लिए की गई थी।

याचिकाकर्ताओं, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

(क) विचाराधीन उत्पाद:

3. विचाराधीन उत्पाद फ़ैरो सिलिकोन है जो कैल्सियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, सल्फर और असोधित फासफोरसयुक्त लौह और सिलिकान का एक मिश्रण है। सिलिकान फ़ैरो सिलिकोन में मुख्य अनुपात में होता है (एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु के रूप में उल्लिखित)। फ़ैरो सिलिकान का सामान्यतः उत्पाद के बाहरी व्यास के मिलिमीटर के रूप में वर्णित होता है।

फ़ैरो सिलिकान का प्राथमिक उपयोग इस्पात और मिश्र इस्पातों के उत्पादन में डिऑक्सिडाइजर के रूप में होता है। फ़ैरो सिलिकान पावर रिएक्टिफायर्स और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के विनिर्माण में भी किया जाता है। फ़ैरो सिलिकान के विभिन्न उपयोगों का निम्नानुसार वर्णन किया जा सकता है:-

- इस्पात के उत्पादन में डिऑक्सिडाइजर
- इस्पात के लिए एक मिश्रण तत्व के रूप में
- इलेक्ट्रिकल ग्रेड इस्पात को बनाने में

- क्षयरोधी और एसिड प्रतिरोधी इस्पात के उत्पादन में
- वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के विनिर्माण में
- इसे कास्ट आइरन में ग्रेफाइटाइजिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है ।

फैरो सिलिकान सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 72 के सीमाशुल्क उपशीर्ष संख्याओं 7202.21 तथा 7202.2100 के अन्तर्गत वर्गीकृत है । जांच के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने सिलिकान के 55% से अधिक के भार वाले फैरो सिलिकान को लिया है । प्राधिकारी विचाराधीन उत्पादन के बारे में प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

(ख) समान वस्तु

घरेलू उद्योग के विचार

4. (i) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित फैरो सिलिकान में कोई अंतर नहीं है जिसका कीमत पर कोई प्रभाव पड़ सकता हो । भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित फैरो सिलिकान भौतिक और रासायनिक गुणों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोगों, उत्पादन विशिष्टताएं, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं के रूप में तुलनीय है । ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है । फैरो सिलिकान के उपभोक्ता इसका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करते हैं । इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित फैरो सिलिकान को पाटनरोधी नियमों के अनुसार समान वस्तु के रूप में माना जाना चाहिए ।

(ii) भारतीय उद्योग और निर्यात करने वाले देशों में विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है । विश्व भर में स्थापित प्रौद्योगिकी प्रगलन प्रक्रिया है । भारतीय उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देशों में फैरो सिलिकान के विनिर्माताओं द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

5. (i) पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(घ) यह विनिर्दिष्ट करता है कि समान वस्तु से अभिप्राय वह वस्तु है जो जांचाधीन उत्पाद जैसी हो, सभी प्रकार से उसके

समान हो या ऐसी वस्तु की अनुपस्थिति में ऐसी वस्तु जिसके गुण जांचाधीन वस्तु के गुणों से काफी मिलते-जुलते हों ।

(ii) फ़ैरो सिलिकान, कैल्सियम, एल्यूमीनियम, कार्बन, सल्फर और असोधित फास्फोरस युक्त लौह और सिलिकान का एक मिश्रण होता है । तथापि, फ़ैरो सिलिकान के उत्पादन के लिए प्रक्रिया के रूप में उपकरण या प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण नहीं है । फ़ैरो सिलिकान का प्राथमिक उपयोग इस्पात और मिश्र इस्पात के उत्पादन में डिआक्सिडाइजर के रूप में किया जाता है । फ़ैरो सिलिकान का उपयोग पावर रेक्टिफायर्स और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स के विनिर्माण में भी किया जाता है । यह स्थापित करने के लिए कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फ़ैरो सिलिकान संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु के जैसी समान वस्तु है, प्राधिकारी द्वारा तकनीकी विशिष्टताएं, विनिर्माण प्रक्रिया, उपयोग तथा कार्य और टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशिष्टताओं पर विचार किया गया है । मै0 टिस्को ने यह बात उठाई है कि उच्च और शुद्धता वाला फ़ैरो सिलिकान जिसका स्थानीय उत्पादन, उत्पादन करने में कठिनाई महसूस करते हैं क्योंकि वे आर एण्ड डी में और इस विषय में प्रतिस्पर्धा करने के लिए विशेषज्ञता हासिल करने हेतु बहुत कम निवेश करते हैं, जैसे कुछ विशिष्ट ग्रेड हैं । तथापि, उनके द्वारा इस बात को इंगित करने के कोई साक्ष्य नहीं दिए गए हैं कि आयातित फ़ैरो सिलिकान घरेलू रूप से उत्पादित फ़ैरो सिलिकान का तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है ।

(iii) प्राधिकारी को मालूम हुआ है कि विवाद का ऐसा कोई पर्याप्त तर्क नहीं है जिसमें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित फ़ैरो सिलिकान आयातित माल से विशेषताओं में काफी मिलता-जुलता है और यह वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों रूपों में संबद्ध देश से आयातित फ़ैरो सिलिकान का प्रति स्थापनीय है । उपरोक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का मानना है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयात किया जा रहा फ़ैरो सिलिकान नियमों के अर्थ के भीतर समान वस्तुएं हैं ।

ग. जांच शुरू करना, उसका आधार और घरेलू उद्योग

6.(i) याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै0 इंडियन मैटल्स फ़ैरो अलायज लिंव (आईएमएफए), भुवनेश्वर द्वारा दायर की गई है । याचिकाकर्त्ताओं ने दावा किया है कि संबद्ध वस्तु के कुल भारतीय उत्पादन में उनका लगभग 47% का हिस्सा बनता है । मै0 हाइटैक इलेक्ट्रो थर्मिक्स एण्ड हाइड्रो पावर लिमिटेड, नई दिल्ली ने घरेलू उत्पादन के 9.92% के आधार के साथ याचिकाकर्त्ता द्वारा दायर की गई याचिका का समर्थन किया

है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि अनन्तिम जांच परिणामों के बाद अन्य घरेलू उत्पादक मै0 वी बी सी फ़ैरो अलायज, हैदराबाद ने भी 15.6% के उत्पादन हिस्से के साथ याचिकाकर्ता को समर्थन देने का विचार व्यक्त किया है । पाटनरोधी नियमों के नियम 5(3) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (क) के अन्तर्गत दिए गए आवेदन के अनुपालन में तब तक कोई जांच नहीं करेगा, जब तक कि वह समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा उक्त आवेदन के संबंध में व्यक्त समर्थन अथवा विरोध की जांच के आधार पर यह निर्धारित न कर ले कि उक्त आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है किन्तु उस स्थिति में कोई जांच शुरू नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25% से कम बनता है । उपनियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आवेदन को उस स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया माना जाएगा यदि इसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों द्वारा किया गया हो जिनका सामूहिक उत्पादन उक्त आवेदन का समर्थन अथवा विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उक्त भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन को 50% से कम बनता हो ।

(ii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे की जांच की, इंडियन फ़ैरो अलायज एसोसिएशन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता कुल घरेलू उत्पादन के 46.89% का हिस्सा रखता है । याचिकाकर्ता और समर्थनकर्ता का कुल भारतीय उत्पादन का 72% हिस्सा बनता है ।

(iii) इस प्रकार, प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता प्रारंभिक जांच परिणाम के प्रयोजनार्थ उपरोक्त नियमों के नियम 5(3)(क) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने के आधार संबंधी मापदण्ड को पूरा करता है । प्राधिकारी उपर्युक्त नियम 2(घ) के अर्थ के भीतर इन याचिकाकर्ता कंपनियों को " घरेलू उद्योग " भी मानते हैं ।

घ. जांच की अवधि

7. प्राधिकारी ने जांच अवधि 1 अप्रैल, 2001 से 31 दिसंबर, 2001 तक की ली है जोकि जांच के लिए सर्वाधिक नवीनतम अवधि है । क्योंकि यह मामला 11 अप्रैल 2002 को शुरू किया गया था । इस अवधि को तिमाहियों के समाप्त होने तथा पूर्ण आंकड़े प्राप्त करने की व्यवहार्यता के कारण भी लिया गया था । प्राधिकारी इस बात

की पुष्टि करते हैं कि पाटनरोधी जांच हेतु नौ माह का समय पर्याप्त एवं उचित है क्योंकि यह उन तीनों तिमाहियों के समकालिक भी है जिनके लिए संगत आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं।

ड. न्यूनतम सीमा

8. जहां तक यह सुनिश्चित करने का संबंध है कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम स्तर से अधिक रहे हैं, प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए डी जी सी आई एण्ड एस के प्रकाशित आंकड़ों का हवाला दिया है।

देश का नाम	मात्रा (एम.टी.)	% आयात हिस्सा
दक्षिण अफ्रीका	552	3.92
मैसिदोनिया	1902.68	13.53

इस प्रकार प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयात न्यूनतम स्तर से अधिक रहे हैं।

9. अन्य विचार: इंडियन फैंरो एलॉयज प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के विचार

- (i) जहाँ तक भारत में दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया से फैंरो सिलिकॉन के आयात की पाटनरोधी जांच के बारे में हमारे विचारों का संबंध है, हम आपको यह सूचित करना चाहेंगे कि फैंरो सिलिकॉन उद्योग चीन, रूस, यूक्रेन और अब दक्षिण अफ्रीका तथा मैसिदोनिया जैसे देशों से भारी मात्रा में और सस्ते आयातों की वजह से पिछले कुछ वर्षों से घटा उठा रहा है।
- (ii) देश में उपलब्ध कुल क्षमता लगभग 1,75,000 टन की है। हम यहाँ यह उल्लेख करना चाहते हैं कि उपर्युक्त देशों से आयातों में वृद्धि के कारण भारत में वर्तमान उत्पादन घट कर 70,000 टन हो गया है। लगभग 50 एकक बंद हो गए हैं और मौजूदा उत्पादन मुश्किल से कुल क्षमता का लगभग 40 है।

- (iii) विश्वेसरैया आयरन इंडस्ट्री लि० द्वारा संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर्स लि० जैसे फैंरो सिलिकॉन के उत्पादकों ने अपने प्रचालन बंद कर दिए हैं क्योंकि वे कम कीमत पर आयातों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ थे। नवभारत फैंरो एलॉयज लि०, इस्पात एलॉयज लि० और अंजनी फैंरो एलॉयज लि० जैसे उत्पादकों ने उपर्युक्त कारणों से फैंरो सिलिकॉन का उत्पादन बंद कर दिया है। एक अन्य प्रमुख उत्पादक मै० वी.बी.सी. फैंरो एलॉयज लि० 1 अप्रैल, 2002 से बंद हो गया है।
- (iv) इस एसोसिएशन ने कई बार फैंरो सिलिकॉन के उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में सरकार से विचार-विमर्श किया और वह फैंरो सिलिकॉन, जिसकी इस देश में भरमार हो गई है, के पाटन के बारे में अत्यधिक चिंतित है। बाद में दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया से हुए आयात गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं।
- (v) फैंरो सिलिकॉन के उत्पादक बिजली टैरिफ तथा संभार तंत्र एवं श्रम लागत सहित सभी अन्य निविष्टियों में वृद्धि के मद्देनजर उत्पादन लागत में भारी बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं। देश में आ रहे सस्ते आयातों से भारतीय उत्पादकों को कीमत में विधिसम्मत वृद्धि करने से वंचित किया गया है।
- (vi) देश में फैंरो एलॉयज के विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह एसोसिएशन इस बात का समर्थन करती है कि 13 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० 7/2002-सी.शु. के तहत लगाए गए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क को उपर्युक्त देशों अर्थात् दक्षिण अफ्रीका तथा मैसिदोनिया के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फैंरो सिलिकॉन के सभी आयातों पर अंतिम रूप से निर्धारित किया जाए ताकि भारतीय उत्पादक व्यावहारिक बन सकें।

प्रकट विवरण पर टिप्पणियां

9क. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु और घरेलू उद्योग की स्थिति के संबंध में प्रकटन विवरण का समर्थन किया

च. पाटन मार्जिन

10. आयातक मै0 टिस्को, कोलकाता के विचार

- (i) हमें इस बात का बेहत खेद है कि दक्षिण अफ्रीका के निर्यातकों ने सामान्य मूल्य निकालने के लिए घरेलू कीमतों की पुष्टि करने हेतु आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं। तथापि, सुनिश्चित लागत का निर्धारण (याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर परिकल्पित) सही नहीं है। एक बेहतर विकल्प डब्ल्यू टी ओ में उपलब्ध है जिसके अनुसार यदि हम दक्षिण अफ्रीका से अन्य गंतव्यों के लिए निर्यात कीमतों की तुलना करते हैं तो हम यह पाते हैं कि ये कीमतें वस्तुतः समान हैं या फिर भारत के लिए कीमतों से भी कम हैं। जांच अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीका ने जिस कीमत पर यू एस ए, जापान और यूरोप को निर्यात किया है वह 523/मी.टन से कम है (1 अ.डा.= 47.50 रु० की दर से 24859/मी.टन की भारित औसत सी आई एफ कीमत जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों में उल्लेख किया गया है)। इस प्रकार यदि हम उस कीमत पर विचार रकते हैं जिस पर दक्षिण अफ्रीका से तीसरे देशों को निर्यात किया गया है तो समुद्री भाड़े आदि के कारण छिटपुट अंतर के अलावा इस बात की निःसंदेह पुष्टि हो जाती है कि भारत के लिए निर्यात कीमतें तीसरे पक्षों के लिए निर्यात कीमतों से तुलनीय हैं और इसलिए उक्त उत्पाद का भारत में पाटन किए जाने का प्रश्न ही नहीं है।
- (ii) समुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बिक्री एवं सामान्य व्यय तथा सामान्य लाभ के प्रभाव को जोड़ने के बाद 336 अ.डा./मी.टन की वास्तविक लागत आधार पर परिकल्पित सामान्य मूल्य 523 अ.डा./मी.टन (सीआईएफ) की निर्यात कीमत से काफी कम है। इस प्रकार याचिकाकर्त्ताओं का यह तर्क कि दक्षिण अफ्रीका द्वारा सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात करके भारत में फैंरो सिलिकॉन का पाटन किया जा रहा है, सच नहीं है और इससे निस्संदेह यह प्रमाणित होता है कि कोई पाटन नहीं हुआ है।

11. घरेलू उद्योग के विचार

- क. जहां तक दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया से सामान्य मूल्य के निर्धारण का संबंध है, संबद्ध देशों से घरेलू बाजार में प्रचलित संबद्ध वस्तु की कीमतों के बारे में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे । याचिकाकर्ता ने आगे यह कहा है कि वह इस संबंध में कोई प्रामाणिक सूचना प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुआ है । याचिकाकर्ता ने उन कीमतों को हासिल करने की कोशिश की जिन पर दक्षिण अफ्रीका तथा मैसिदोनिया के निर्यातक अन्य देशों को संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रहे हैं । तथापि, इस संबंध में किसी प्रकाशित सूचना का पता नहीं चल सका । अतः, याचिकाकर्ता ने प्रमुख कच्ची सामग्रियों के लिए मानक खपत मानदंडों और उपयोगिताओं के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । याचिकाकर्ता ने पूर्ववर्ती मामलों का उल्लेख किया है जिनमें सामान्य मूल्य का निर्धारण उन्हीं संबद्ध देशों से परिकलित मूल्य के आधार पर किया गया है ।
- ख. जहां तक निर्यात कीमत की गणना का संबंध है, याचिकाकर्ता ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से हुए आयातों की वास्तविक मात्रा और उनकी कीमतों के बारे में डी जी सी आई एंड एस की सूचना पर विचार किया है । याचिकाकर्ता ने समायोजन करने के बाद कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का परिकलन किया है । याचिकाकर्ता ने मैसिदोनिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए पाटन मार्जिन निकाला है ।
- ग. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इससे पूर्व रूस, यूक्रेन और चीन के निर्यातकों द्वारा उक्त उत्पाद के पाटन की जांच की थी । इसके परिणामस्वरूप पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था जो अब तक लागू है । इन स्रोतों का पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से घरेलू उद्योग अपना उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा को बढ़ाने में समर्थ हुआ है । तथापि, संबद्ध देशों के उत्पादकों ने संबद्ध वस्तु का पाटन शुरू कर दिया है जिससे घरेलू उद्योग कीमत को इष्टतम स्तर तक बढ़ाने से वंचित हुआ है । याचिकाकर्ता ने आगे कहा है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच घरेलू उद्योग को पहले हुई क्षति के आलोक में की जा सकती है ।
- घ. मैसिदोनिया और दक्षिण अफ्रीका के किसी भी निर्यातक ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया है । इस प्रकार निर्यातकों ने वर्तमान जांच में असहयोग को प्राथमिकता दी है । इसलिए प्राधिकारी भारतीय पाटनरोधी नियमों के अनुसरण में उचित उपलब्ध सूचना के अनुसार कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह न्यायसंगत हैं ।

11 क. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग की टिप्पणियां

याचिकाकर्ता पाटन के संबंध में प्रकटन विवरण का समर्थन करते हैं। टिस्को के तर्क के संबंध में याचिकाकर्ता अनुरोध करते हैं कि टिस्को एक आयातक होने के कारण पाटन निर्धारण पर कोई तक नहीं दे सकते हैं। यदि दक्षिण अफ्रीकी निर्यातक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को जवाब देना अनावश्यक समझते हों तो टिस्को यह तर्क नहीं दे सकता कि उस कीमत को ध्यान में रखते हुए जिस पर दक्षिण अफ्रीका से अन्य देशों को माल का निर्यात हुआ होगा, कोई पाटन नहीं हुआ है।

12. प्राधिकारी द्वारा जांच

धारा 9 क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:-

- (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथानिर्दिष्ट तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो: या
- (ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य या तो:-
 - (क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु का उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य: या
 - (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निश्चित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ वस्तु मूल के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत:

बशर्ते कि वस्तु का आयात जब मूलता के देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया हो तथा जहां वस्तु निर्यात के देश से केवल गुजरी हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण मूलता के देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

- (iii) प्राधिकारी नोट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया के किसी भी निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के साथ संलग्न अनुबंध के संबंध में कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है। चूंकि संबद्ध वस्तु के घरेलू बिक्री कीमत ढांचे के बारे में सूचना, दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया में इसकी उत्पादन लागत और प्रश्नावली के अनुसार कोई अन्य सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य पर विश्वास करके कार्रवाई की है। याचिकाकर्ता ने दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया के संबंध में सामान्य मूल्य का दावा उत्पादन की परिकलित लागत के आधार पर किया है। प्राधिकारी पाते हैं कि किसी भी निर्यातक ने कोई ऐसी सूचना नहीं दी है जिससे वे घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने में सफल हो सकें। सम्बद्ध देश को निर्यातकों से निर्धारित प्रपत्र में किसी उत्तर के अभाव में प्राधिकारी उपरोक्त नियम 6(8) अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सम्बद्ध देशों से निर्यातों के संबंध में जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।
- (iv) तदनुसार प्राधिकारी ने लागू समायोजनों के साथ उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य क्रमशः *** यूएस डालर/मी.टन और *** यूएस डालर/मी.टन है।
- (v) यद्यपि याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में सूचना प्रस्तुत कर दी है तथापि प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से आयातों के लिए डी जी सी आई एंड एस से प्राप्त आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका ने जांच अवधि के दौरान 288833.7 अमरीकी डालर की कीमत पर 552 मी.टन निर्यात किया है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना (डीजीसीआईएंडएस) के अनुसार भारत औसत सी आई एफ कीमत 24859 रु०/मी.टन निर्धारित की गई है। यूएस डालर *** /मी.टन समुद्री भाड़े के रूप में, *** % समुद्री बीमा प्रभारों के रूप में और यूएस डालर *** /मी.टन पत्तन व्ययों और परिवहन प्रभारों(अन्तर्राज्यीय) के रूप में मानने के पश्चात् कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया है।
- (vi) जहां तक मैसिदोनिया की निर्यात कीमत के निर्धारण का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं मैसिदोनिया ने जांच अवधि के दौरान यूएस डालर 775389 की कीमत पर 1902.68 मी.टन का निर्यात किया है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध

सूचना (डीजीसीआईएंडएस) के अनुसार भारत औसत सी आई एफ कीमत यूएसडालर 407.52/मी.टन निर्धारित की गई है। समुद्री भाड़े के रूप में यूएस डालर *** /मी.टन, समुद्री बीमा प्रभाओं के रूप में *** % और पत्ततन व्यय और परिवहन प्रभाओं(अन्तर्राज्यीय) के लिए यूएस डालर *** /मी.टन मानने के पश्चात कारखानागत निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है। भारतीय इंडेंटिंग एजेंट के लिए *** % की दर पर कमीशन को प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अस्वीकार कर दिया गया है। इन कारणों से किए गए समायोजनों के पश्चात् कारखानागत एफ ओ बी कीमत 47.51 रू0 = 1 अमरीकी डालर की औसत विनिमय दर पर *** रू0/मी.टन अथवा *** यूएस डालर /मी.टन अथवा ***यूएस डालर /मी.टन आंकी गई है।

- (vii) दक्षिण अफ्रीका के लिए पाटन मार्जिन***यूएस डालर अथवा निर्यात कीमत का 39.38% बैठता है और मैसिदोनिया के लिए पाटन मार्जिन ***यूएस डालर अथवा निर्यात कीमत का 95.48% बैठता है।

पाटन मार्जिन			
निर्यातक देश	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन %
दक्षिण अफ्रीका: सभी निर्यातक	***	***	39.38
मैसिदोनिया: सभी निर्यातक	***	***	95.48

छ. क्षति

13. आयातक मै0 टिस्को के विचार

- (i) घरेलू उत्पादक जिनके पास आबद्ध विद्युत का सस्ता स्रोत नहीं है, के सामने इस तथ्य के कारण क्षति का खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा है कि कई देश (रूस, यूक्रेन और चीन) और अब दक्षिण अफ्रीका तथा मैसिदोनिया भारत में फैंरो सिलिकॉन का पाटन कर रहे हैं परन्तु इस तथ्य के कारण है कि भारत में बिजली की अत्यधिक लागत होने के कारण (दक्षिण अफ्रीका से 5/6 गुणा) फैंरो सिलिकॉन का उत्पादन (जिसमें प्रति मी.टन 9000 के डब्ल्यू एच से अधिक खपत होती है) वैश्विक स्तर के अनुसार बिल्कुल प्रतिस्पर्धी नहीं हैं।

- (ii) इसके अतिरिक्त फैंरो सिलिकॉन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें वर्षों से कम होती रही हैं जिसके फलस्वरूप भारतीय उत्पादक, जो पहले ही विद्युत की अधिक लागत से ग्रस्त हैं, अब वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी नहीं रहे हैं इसलिए क्षति के खतरे का सामना कर रहे हैं, हालांकि फैंरो सिलिकॉन मौजूदा बाजारी कीमतों पर आयात (न कि पाटन) किया जा रहा है। इसलिए यह साबित होता है कि संबद्ध देशों से फैंरो सिलिकॉन के आयातों और घरेलू उत्पादकों को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध (जैसाकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 2 में प्रावधान है) नहीं है।
- (iii) इसलिए यदि संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो आयातकों के पास कोई विकल्प नहीं होगा सिवाय इसके कि संबद्ध स्रोतों के प्राप्त होने तक वे वैकल्पिक अवस्थितियों का पता लगाएं। वास्तव में याचिकाकर्त्ता कंपनी का आशय यह सुनिश्चित करना है कि अधिक से अधिक देश पाटनरोधी शुल्क के दायरे में शामिल किए जाएं और भारतीय बाजार वैश्वीकरण के दबाव से अलग हो जाएं। इस प्रकार याचिकाकर्त्ता कंपनी का उद्देश्य एक संरक्षित बाजार स्थल उत्पन्न करना है जिसमें वह लगातार ग्राहकों का शोषण कर सके और अत्याधिक लाभ अर्जित कर सके।

14. आयातक मै0 जिंदल स्टील्स लि0 के विचार

1. आवेदन और प्रारंभिक जांच परिणामों से यह देखा गया है कि आवेदन उन याचिकाकर्त्ताओं द्वारा किया गया है जिन्होंने घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने का दावा किया है। याचिकाकर्त्ताओं का जांच अवधि के दौरान उत्पादन में 40.79% हिस्सा है जबकि समर्थकों का हिस्सा घरेलू उत्पादन में 9.92% है। सादर निवेदन है कि हालांकि याचिकाकर्त्ता घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन करने की स्थिति में हो सकते हैं परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि याचिका में विभिन्न क्षति मानदंड जैसे बाजार का हिस्सा, कीमतें और कारणात्मक संबंध की जांच के लिए अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराई गई हो।
2. उपयुक्त के साथ बगैर किसी वैमनस्य के हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि घरेलू उद्योग को सम्बद्ध देशों से आयातों के कारण कोई क्षति नहीं पहुंची है। क्षति के मापदण्डों से किसी क्षति की मौजूदगी मालूम नहीं होती है। इसी समय कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को दर्शाने वाला मुश्किल से कोई कारक जो अनन्तिम शुल्क लगाने के लिए भी एक पूर्वापेक्षा है।
3. बिक्रियों, उत्पादन और क्षमता उपयोग जैसे क्षति मापदण्डों से पिछले वर्षों की तुलना से वृद्धि मालूम होती है और उनकी भंडार सूचियों में भी पिछले वर्षों से

जांच अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त रोजगार, वेतन, नकदी प्रवाह, विकास और निवेश बढ़ाने की योग्यता जैसे अन्य क्षति मापदण्डों के संबंध में भी कोई टिप्पणियाँ नहीं की गई हैं। इसके अलावा, जब आयातों के बाजार के हिस्से की समस्त आयातों के साथ तुलना की गई तो ऐसी कोई तुलना घरेलू उद्योग के हिस्से में परिवर्तनों के साथ वर्षों की समग्र खपत के साथ नहीं की गइल है। जैसाकि निदेशकों की रिपोर्ट में उल्लेख है उनका वित्तीय कार्य निष्पादन प्रतिकूल और दबी हुई बाजार की परिस्थितियों द्वारा प्रभावित हुआ है और घाटे की स्थिति सम्बद्ध देशों से आयातों के कारण कही जा सकती है। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने यह कहने के अलावा कि उनकी कीमतें आयातों के कारण प्रभावित हुई हैं, घरेलू कीमतों के प्रभावित करने वाले घटकों का कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है।

4. आयातक ने यह चिंता व्यक्त की है कि याचिकाकर्ताओं को घटे पाटन के अलावा अन्य घटकों से हो सकते हैं। याचिकाकर्ताओं का समस्त प्रयास सभी स्रोतों से आपूर्तियाँ रोकने का रहा है ताकि वे एकाधिकारिक कीमतें वसूल कर सकें। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि याचिकाकर्ताओं के क्षति के आंकड़ों के विश्लेषण से कारणात्मक संबंध की कोई उपस्थिति साबित नहीं होती है।

14 क. मै0 जिंदल स्ट्रिप्स लि0 द्वारा प्रकटन विवरण से संबंधित टिप्पणियाँ

- i. घरेलू उद्योग से संबंधित क्षति के सभी मापदण्डों से पहले की अवधि की तुलना में सुधार हुआ है और यह मानने योग्य नहीं है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति पहुंची है। जहां तक घाटों का संबंध है, यह समझा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को तथाकथित पाटन से पहले भी घाटे हो रहे थे और उनकी स्थिति में केवल जांच अवधि के दौरान ही सुधार हुआ है। इस संबंध में केवल यही निवेदन है कि कम मूल्य पर बिक्री कारक समझा गया है, वस्तुतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 के अन्तर्गत की गई परिकल्पना के अनुसार क्षति का कारक नहीं है। सादर निवेदन है कि गैर-क्षतिकारक कीमत वसूल करने की उनकी अयोग्यता के आधार पर क्षति का संदर्भ देने के लिए अनुमति प्राप्त नहीं होगी।
- ii. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित कीमत में कटौती का विश्लेषण गलत मालूम होता है क्योंकि मूल्य में कटौती देशवार किए जाने की आवश्यकता होती है। तथाकथित पाटित आयातों और तथाकथित परन्तु अनुपस्थित घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध बिल्कुल विद्यमान नहीं है।

- iii. जहाँ तक बाजार के हिस्से का संबंध है, घरेलू उद्योग ने अपने बाजार के हिस्से में सुधार किया है और यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई संभव कारण नहीं हो सकता है।

15. घरेलू उद्योग के विचार

1. याचिकाकर्ता ने यह अभ्यावेदन किया है कि फैंरो सिलिकॉन के संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से और भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के अनुसार तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन के अनुसार और भारत में संबद्ध वस्तु की मांग बके अनुसार भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। उन्होंने संबद्ध देशों की निर्यात कीमत में काफी कमी का उल्लेख किया है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जिसके परिणामस्वरूप कीमत में कटौती करनी पड़ी है। निर्यात कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है और घरेलू उद्योग की गैर-क्षतिकारक कीमत से भी कम है तथा उन सभी देशों के आयातों की पहुंच कीमत से कम है जिन पर पाटनरोधी शुल्क लगाए गए हैं।
2. याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में वृद्धि को घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत, निश्चित ऊपरी खर्चों को कम करने के लिए अधिक उत्पादन करने और अनेक देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग के प्रयासों के साथ देखा जाना है। घरेलू उद्योग को उत्पादन में काफी सुधार होने के बावजूद घाटा उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसी प्रकार बढ़ी हुई बिक्री की मात्रा को भी अनेक देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के संदर्भ में देखा जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि घरेलू उद्योग उत्पादन में वृद्धि और संबद्ध वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि के बावजूद आशाजनक स्तरों तक कीमतें नहीं बढ़ा सका है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग को अनेक स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद निरंतर वित्तीय घाटे हो रहे हैं। कुछ मापदण्डों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्रियां, स्टॉक और प्रति यूनिट घाटों से इस कारणवश सुधार मालूम होता है कि इन मापदण्डों में सुधार अनेक स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के कारण हुआ था।
3. जहाँ तक ज़िंदल के इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता उद्योग के घाटे पिछले वर्ष की तुलना में 58% तक कम हो गए हैं जब वास्तव में आयात कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में कम हुई हैं तब याचिकाकर्ता यह अभ्यावेदन करते हैं

कि जिंदल द्वारा दी गई तालिका में नीचे पुनः परिकलित तालिका द्वारा भ्रांति सिद्ध होती है ।

वर्ष	मैसिदोनिया से आयात			दक्षिण अफ्रीका से आयात			कुल आयात		
	मात्रा, मी. टन	मूल्य लाख रु०	दर रु०/ मी. टन	मात्रा, मी. टन	मूल्य लाख रु०	दर रु०/ मी. टन	मात्रा, मी. टन	मूल्य लाख रु०	दर रु०/ मी. टन
1999-0				20	4.03	20150	20	4.03	20150
2000-01	54	11.86	21963	54.6	28.52	52234	108.6	40.38	37182
जांच अवधि	1902.7	371.91	19546	552	137.22	24859	2454.7	509.13	20741

- यह मालूम होगा कि तालिका में 52.23 रु० प्रति किग्रा. की दर पर फैंरो सिलिकॉन का आयात दर्शाया गया है । क्या जिंदल का यह तर्क कि फैंरो सिलिकॉन सीमाशुल्क से मुक्त 52.23 रु० की औसत सीआईएफ कीमत पर भारत में (और जिंदल सामग्री को खरीदेगा) किया गया है । जिंदल ने साधारण तौर पर आंकड़ों में संभव गलती की अनदेखी की है ।
- तालिका में भ्रामकता और जिंदल द्वारा दिया गया तर्क जो अन्य देशों के संबंध में सूचना से एक बार पुनः साबित होता है, की भी जांच की जाए । विभिन्न देशों से आयातों की सूचना याचिकाकर्ता द्वारा पहले उपलब्ध कराई गई थी । यह भी मालूम होगा कि विभिन्न देशों से बहुत ही कम कीमतों पर आयात (जिन पर अब शुल्क लगा हुआ है) उपलब्ध है । इस प्रकार यह तर्क देना उचित नहीं होगा कि दक्षिण अफ्रीका से आयात कीमत 52 रु० से घटकर 25 रु० हो गई थी जबकि घरेलू उद्योग के घाटे भी कम हो गए थे । पिछले वर्षों में घरेलू उद्योग को घाटे अन्य देशों से पाटित आयात के कारण हुए थे ।
- घरेलू उद्योग के लिए आर ओ आई निरन्तर नकारात्मक है और उत्पादकता में सुधारा के बावजूद घरेलू उद्योग को पाटन के कारण बाजार में उपलब्ध कम ईष्टतम कीमतों के कारण वित्तीय घाटे हुए हैं । कंपनी के पास सांविधिक विनियमों के कारण कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है । वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग विस्तार और निवेश के लिए अपने पूंजीगत मामले को बढ़ाने की सोच भी नहीं सकता है ।

प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग की टिप्पणियाँ

15क. अनेक क्षति मापदण्डों में सुधार के बारे में मै0 जिंदल स्ट्रिप्स लि0 के तर्क में बाजार की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया गया है। जिंदल द्वारा इस बात को आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया है कि पहली अवधि जिसके साथ जिंदल ने तुलना की है और निष्कर्ष निकाले हैं, पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई क्षति की अवधि थी। हमने चीन जनवादी गणराज्य से फैंरो सिलिकॉन मैगनीज के मामले में ई सी का एक निर्णय (काउंसल संदर्भ संख्या 495/98 दिनांक 23 फरवरी 1998) प्रस्तुत किया है जिसमें स्पष्ट रूप से यह माना गया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति का मूल्यांकन करते हुए यह ध्यान में रखना होता है कि घरेलू उद्योग बाजार में उत्पाद के पहले वाले पाटन से उबर रहा था।

प्राधिकारी द्वारा जांच

16. घरेलू उद्योग को क्षति का विश्लेषण रिकार्ड में उपलब्ध सूचना और पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई जांच के आधार पर किया गया है। जहाँ तक कुछ आयातों द्वारा की गई टिप्पणी का संबंध है, प्राधिकारी ने मै0 आई एम एफ ए, भुवनेश्वर और मै0 वी बी सी फैंरो एलॉयल, हैदराबाद के संबंध में क्षति की सूचना का निर्धारण किया है जिनका अब घरेलू उद्योग में 62% हिस्सा है। विभिन्न क्षति मापदण्डों को तैयार करने का उनका मूल्यांकन करने के लिए यह तथ्य ध्यान में रखा जाए कि घरेलू उद्योग के समक्ष फैंरो सिलिकॉन की बढ़ती हुई मांग थी जिसे उत्पादन रूस, चीन जनवादी गणराज्य तथा यूक्रेन के मूल से अथवा वहां से निर्यातित आयातों पर इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क के संदर्भ में पूरा किया जाना है। इस प्रकार के उपायों के विशिष्ट प्रभाव को 1998-99 के बाद की समरूवधि के लिए विभिन्न क्षति कारकों का विश्लेषण करते समय ध्यान में रखा गया है। घरेलू उद्योग को हुई क्षति के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदण्डों का विश्लेषण किया गया है।

पाटित आयातों की मात्रा और बाजार में हिस्सा

17. प्राधिकारी ने जांच की अवधि और पहले के वर्षों में संबद्ध देशों से निर्यातों की मात्रा से संबंधित जानकारी का निरीक्षण किया है। जांच की अवधि के दौरान दोनो संबद्ध देशों से हुए आयात 2454 मी.टन तथा 3272 मी.टन थे (वार्षिक)। वर्ष 2000-2001 के दौरान ये आयात 108 मी.टन थे (डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों के

अनुसार)। संबद्ध देशों से इन आयातों का बाजार हिस्सा, वर्ष 1999-2000 में 0.1% वर्ष 2000-01 में 0.61% तथा जांच अवधि के दौरान 17.47% था। पिछले वर्ष 2000-01 की तुलना में, जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्से में मात्रात्मक वृद्धि दर्ज हुई। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पिछले वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। यद्यपि 1999-00 से 2000-01 के बीच बाजार हिस्से में सुधार हुआ है, विशेषतः रूस, यूक्रेन तथा चीन जनवादी गणराज्य मूल के आयातों के विरुद्ध निश्चयात्मक उपायों को लागू करने के बाद। फिर भी यह नोट किया गया है कि इस वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग अपनी उस स्थिति को पुनर्प्राप्त नहीं कर पाया है जो संबद्ध देशों से क्षतिपूर्ण पाटन के पूर्व थी।

आयात वृद्धि					
	यूनिट	98-99	99-00	00-01	वार्षिक जांच अवधि
मैसिदोनिया	एमटी	0	0	54	2537
दक्षिण अफ्रीका	एमटी	100	20	55	736
संबद्ध देश	एमटी	100	20	109	3273
एडी के साथ देश	एमटी	2615	9857	6617	2686
अन्य	एमटी	1660	10847	11196	12779
कुल	एमटी	4375	20719	17921	18738

आयात में बाजार हिस्सा					
	यूनिट	98-99	99-00	00-01	वार्षिक जांच अवधि
संबद्ध देश	%	2.29	0.1	0.61	17.47
एडी के साथ देश	%	59.78	47.58	36.92	14.34
अन्य	%	37.94	52.33	62.47	68.2
कुल	%	100	100	100	100

आयात में मांग हिस्सा					
	यूनिट	98-99	99-00	00-01	वार्षिक जांच अवधि

संबद्ध देश	%	0.16	0.03	0.13	3.64
एडी के साथ देश	%	4.24	12.8	7.76	2.98
अन्य	%	2.69	14.08	13.13	14.2
घरेलू उद्योग	%	45.58	37.86	42.36	41.68
भारतीय उद्योग	%	92.9	73.09	78.98	79.17

उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

18. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। जहां घरेलू उद्योग की क्षमता समान रही है वहीं, उच्च उत्पादन के कारण घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। तथापि, संबद्ध उत्पादों की मांग में वृद्धि तथा अन्य स्रोतों से पाटनरोधी शुल्कों के लगाए जाने की स्थिति में क्षमता उपयोग की दर में इस वृद्धि का स्तर सामान्य ही रहा है।

बिक्री मात्रा

19. उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी की बिक्री मात्रा में वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि बिक्री मात्रा में वृद्धि को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तुओं की खपत में वृद्धि हुई है। अतः घरेलू उद्योग को इस सकारात्मक बाजार स्थिति से कुछ लाभ हुआ है। तथापि, लाभप्रदता अब भी नकारात्मक स्थिति में हैं। आगे यह नोट किया गया है कि बिक्री में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा भी हो रहा है, क्योंकि वे कीमत को उस स्तर तक बढ़ाने में असफल रहे हैं, जिससे उत्पादन की पूरी लागत की पूर्ति की जा सके।

कीमत कटौती तथा कीमत बिक्री

20. घरेलू उद्योग में पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमों के अनुबंध-ii के नियम (iv) में यह कहा गया है:

“घरेलू उद्योग की चिंताओं पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों का एक मूल्यांकन करना और उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों को मूल्यांकन करना शामिल होगा, इसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्राप्ति या क्षमता का उपयोग: कीमतों को प्रभावित करने

वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा: नकद प्रवाह, सामान, रोजगार, मजदूरी वृद्धि, पूंजीगत निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं ।

संबद्ध देशों से कीमत कटौती

कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचारार्थ यह जांच करना आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है या क्या अन्यथा ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों में भारी कमी करना है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना निवल बिक्री प्राप्तियों के साथ की है और यह पाया है कि संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा संचयी रूप से महत्वपूर्ण कीमत कटौती की गई है । आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्तियों से अत्यधिक कम पाया गया है ।

संबद्ध देशों से कम कीमतों पर बिक्री

21. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस दावे की भी जांच की है कि घरेलू उद्योग वित्तीय घाटों के कारण नुकसान उठा रहे हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमतों पर बिक्री क्षति का मूल्यांकन करने में एक प्रमुख संकेतक है । प्राधिकारी ने एक उचित बिक्री कीमत निर्धारित की और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा जानने के लिए इसकी तुलना पहुंच मूल्य से की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातों का घरेलू बाजार में कीमतों पर महत्वपूर्ण रूप से हास तथा कमी का प्रभाव है, जिसके चलते दोनों संबद्ध देशों से पाटित आयातों के मद्देनजर घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमतों को क्षतिरहित स्तर तक बढ़ाने में असमर्थ है । इस प्रकार प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उस कीमत से अत्यधिक कम है, जिस पर घरेलू उद्योग को अपनी उत्पादन लागत वसूल करने तथा तर्कसंगत लाभ कमाने में सक्षम हो पाता ।

क्षति मापदंड					
		98-99	99-00	00-01	वार्षिक जांच अवधि
मापदंड	यूनिट				
क्षमता *	एमटी	60,000	60,000	60,000	60,000
आईएमएफए	एमटी	45000	45000	45000	45000
वीबीसी	एमटी	15000	15000	15000	15000

उत्पादन*	एमटी	32792	37796	40829	45704
आईएमएफए	एमटी	22319	26731	30763	33391
वीबीसी	एमटीद	10473	11065	10066	12313
क्षमता उपयोग*	%	54.65	62.99	68.05	76.17
बिक्री*	इंडेक्स	100	103.77	128.58	133.43
खुला स्टॉक*	इंडेक्स	100	44.89	64.75	28.43
क्लोजिंग स्टॉक*	इंडेक्स	100	144.26	63.33	42.52
उत्पादन लागत*	इंडेक्स	100	96.1	96.76	95.19
नेट बिक्री रिलाइजेशन *	इंडेक्स	100	97.34	95.39	96.77
लाभ*	इंडेक्स	100	73.44	121.71	66.45
उत्पाद लाभ*	इंडेक्स	-100	-74.31	- 140.437	-101.934
वेतन और मजदूरी	इंडेक्स	100	103	122	126
नकद लाभ	इंडेक्स	-100	-55.3	-170	-78.82
पूंजी पर वापसी*	इंडेक्स	-1000	-59.18	-124.9	-92.94
रोजगार*	इंडेक्स	100	101.97	98.09	94.10
उत्पादकता*	इंडेक्स	100	113.04	126.93	148.12
बिक्री में बढ़ोतरी	%		3.77	23.9	3.77

* आईएमएफए और बीबीसी

इस प्रकार, पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को तर्कसंगत कीमत प्राप्त करने के लिए उचित कीमत वृद्धि करने से रोका है। बिक्री कीमतों के कारण उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत की वसूली नहीं हुई और इसके चलते वित्तीय घाटे उठाने पड़े हैं। वर्ष 2000-01 की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में मामूली वृद्धि हुई। तथापि, यह भी पाटित आयातों का कारण क्षति रहित कीमत से कम है।

रोजगार एवं मजदूरी

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। मजदूरी/वेतन में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है।

भण्डार सूची

23. वस्तु सूची में आवधिक रूप से कमी हुई है। यहां प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले वर्ष की वह अवधि जिसकी तुलना जांच अवधि के साथ की जा रही है, ऐसी अवधि है जब उद्योग ने परिवर्तित स्रोतों से पाटन का सामना किया है।

आरओआई और नकद लाभ

24. घरेलू उद्योग पिछले 4 वर्षों से ऋणात्मक नकद लाभ उठा रहा है और नकद प्रवाह की स्थिति भी खराब है।

विकास, पूंजी पर आय और पूंजी जुटाने की क्षमता

25. जांच अवधि के दौरान कंपनी पिछले वर्षों की तुलना में 3.7% की वृद्धि दर रजिस्टर करने में सक्षम हुई है। यह भी नोट किया गया है कि उत्पादन के लिए सुविधाओं के उच्चतर उपयोग और संबद्ध उत्पाद की बिक्री के कारण प्रयुक्त पूंजी पिछले वर्षों से बढ़ गई है। तथापि, प्रयुक्त पूंजी में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान और पूर्व वर्षों में हानि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि प्रयुक्त पूंजी पर आय में आगे गिरावट नहीं आई है और उसने मामूली सुधार प्रदर्शित किया है। तथापि, इसे इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि स्वयं प्रयुक्त पूंजी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि घरेलू उद्योग का नकदी प्रवाह, आर ओ आई आर लाभप्रदता-सभी ऋणात्मक रहे हैं, जो घरेलू उद्योग की नई पूंजी जुटाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव लेगा।

अन्य यूनिटों का बंद होना:

26. मै0 आईएफएपीए द्वारा दावा किया गया है कि भारतीय बाजार में माल के लगातार पाटन के कारण कई कंपनियों ने एक के बाद एक संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन स्थगित कर दिया है। यह भी नोट किया गया है कि संबद्ध देशों से पाटन के कारण कई इकाईयों ने उत्पादन बंद कर दिया है। यह भी नोट किया गया है कि एक अन्य घरेलू उत्पादक मै0 हाई टेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स एवं हाइड्रोपावर लि0 को संबद्ध वस्तु के उत्पादन के कारण पर्याप्त हानि हुई है जैसाकि तुलन-पत्र में रिपोर्ट किया गया है। यद्यपि प्राधिकारी ने अपूर्ण एवं अपर्याप्त आंकड़ों के कारण इस फर्म की लागत सूचना को अलग कर दिया है तथापि यह नोट किया जाता है कि इस कंपनी को अत्यधिक हानि उठानी पड़ रही है।

27. संक्षेप में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि:

1. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों में समग्र रूप में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन आयातों में भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों की तुलना में भी वृद्धि हुई है।
2. संबद्ध देशों से आयातों में घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई है और भारत में संबद्ध वस्तु की मांग की तुलना में भी वृद्धि हुई है।
3. निर्यात कीमतों में अत्यधिक गिरावट आई है और संबद्ध देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।
4. याचिकाकर्त्ता को कम कीमत पर बिक्री को इसलिए भी सहना पड़ रहा है क्योंकि संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत क्षति-रहित कीमत से या घरेलू उद्योग की उचित बिक्री कीमत से कम है।
5. पाटित आयात घरेलू उद्योग को क्षति रहित कीमत के स्तर तक कीमत वृद्धि को प्रभावित करने से रोक रहे हैं। बड़ी संख्या में स्रोतों से लगातार पाटन के परिप्रेक्ष्य में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता ईष्टतम से कम बनी हुई है। याचिकाकर्त्ता को कीमत ह्रास/न्युनीकरण का सामना करना पड़ रहा है चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत से कम है।
6. उपयुक्त अभिमतों के मद्देनजर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऊपर सूचीबद्ध किए गए विभिन्न मापदण्डों से स्पष्टतौर पर यह पता चलता है कि आयातों में समग्र रूप में तथा घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में और भारत में मांग के संबंध में भी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से निर्यात की कीमत में गिरावट के कारण आयातों से घरेलू उद्योग की कीमत में संचयी रूप से कटौती हो रही है और उसे प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति-रहित कीमत के स्तर तक विधिसम्मत कीमत वृद्धि करने से रोका जा रहा है। आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग द्वारा कम कीमत पर बिक्री की जा रही है और अनेक स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता ईष्टतम से कम रही है।
7. जहाँ तक प्रयोक्ता उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए इस अभिमत का संबंध है कि घरेलू उद्योग के पास विद्युत का अपना खुद का स्रोत है वह इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क के रूप में कोई अन्य लाभ अनपेक्षित है, प्राधिकारी आई एम एफ ए द्वारा रखे गए रिकार्डों का अध्ययन करने के बाद यह नोट करते हैं कि याचिकाकर्त्ता अपनी सहायक कंपनी से राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा सामान्यतः प्रभारित टैरिफ से काफी सस्ती दर पर विद्युत प्राप्त कर रहा है। तथापि, सस्ती

लागत पर विद्युत प्राप्त करने के बाद भी घरेलू उद्योग अपनी उत्पादन लागत वसूल करने में सक्षम नहीं रहा है ।

ज. क्षति का संचयी निर्धारण

27.क. अनुबंध-ii (iii) के अनुसार ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देशों से उत्पाद के आयातों पर पाटन रोधी जांच की जा रही हो तो प्राधिकारी के लिए ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है । जब वह यह निर्धारण करते हैं कि (क) प्रत्येक देश से आयात के संबंध में साबित पाटन मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में 2% से अधिक व्यक्त किया गया हो और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयात का प्रत्येक देश से आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उचित हो । प्राधिकारी को यह मालूम हुआ है कि प्रत्येक संबद्ध देश में पाटन मार्जिन 2% से अधिक है और प्रत्येक देश से आयातों की मात्रा भी 3% से अधिक है । प्राधिकारी को यह भी मालूम हुआ है कि घरेलू तौर पर उत्पादित समान वस्तु पर संबद्ध वस्तु के आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन करना उचित है और यह भी मालूम हुआ है कि घरेलू उद्योग पर संबद्ध वस्तु के आयातों द्वारा क्षति का संचयी प्रभाव हुआ है।

उपर्युक्त आर्थिक मापदंडों से संचयी एवं सामूहिक रूप से यह प्रमाणित होता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

झ. कारणात्मक संबंध के बारे में प्राधिकारी द्वारा जांच

28. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-2 (v) में यह उल्लेख है कि इस बात को प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त अनुबंध के पैरा 2 और 4 में किए गए निर्धारण के अनुसार पाटन के प्रभावों के जरिए घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है । पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रदर्शन निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष संगत साक्ष्य की जांच पर आधारित होगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पाटित आयातों की बजाय ऐसे किसी ज्ञात कारक की जांच भी की जाएगी जिससे उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और इन कारकों द्वारा हुई क्षति का कारण पाटित आयात नहीं होने चाहिए । इस संबंध में जो कारक प्रासंगिक हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं - पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा एवं मूल्य, मांग में कमी अथवा खपत की पद्धतियों में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यापार तथा

विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी विकास तथा निर्यात निष्पादन एवं घरेलू उद्योग की उत्पादकता ।

घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारण के बारे में अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के नियम V के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात कारकों के प्रभाव और उक्त उद्योग की स्थिति पर उनके परिणामों की जांच की । पाटित आयातों से भिन्न जिन ज्ञात कारकों से उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, उनकी जांच भी यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि इन अन्य कारकों द्वारा हुई संभावित क्षति पाटित आयातों के कारण नहीं हुई थी ।

(i) पाटित आयातों का प्रभाव

वर्ष 1998-99 और जांच अवधि के बीच कुल आयातों के अनुपात के रूप में संबद्ध देशों से पाटित आयातों में मात्रा के रूप में अत्यधिक वृद्धि (57.44% से 98.34% तक) हुई है और यह मांग में कुल हिस्सा 1998-99 में 0.16% से बढ़कर जांच अवधि में 3.65% हो गया है । जहाँ तक निर्यात कीमतों का संबंध है इनमें संपूर्ण अवधि के दौरान गिरावट आई है और औसतन ***% तक (संबद्ध देशों से) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हुई है । इसके अलावा कटौती संबंधी आंकड़ों से पाटित आयातों का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित नहीं होता है क्योंकि घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास हुआ था । पाटित आयातों की कीमत समूची जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमत से कम रही थी और इससे उस पर दबाव बना था जिससे घरेलू उद्योग कीमतें कम करने के लिए बाध्य हुआ । अतः, यह माना जाता है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है ।

(ii) अन्य कारक: अन्य उत्पादकों का निष्पादन:

हितबद्ध पार्टियों द्वारा यह दावा किया गया है कि फैंरो सिलिकॉन का विनिर्माण करने वाले अनेक उद्योग संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण बंद हो गए हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इनमें से कुछ उद्योग जांच अवधि से पूर्व बंद हो गए थे और अनेक स्रोतों से लगातार पाटन इन एककों के बंद होने के कारणों में से एक कारण हो सकता है ।

(iii) असंबद्ध देशों से आयात

प्राधिकारी ने वर्ष 98-99 से और जांच अवधि के दौरान असंबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और मूल्य का विश्लेषण किया है और यह नोट किया है कि असंबद्ध देशों का

बाजार हिस्सा (संबद्ध देशों तथा शुल्क लगाए गए देशों को छोड़कर) 1998-99 में 37.94% से बढ़कर जांच अवधि के दौरान 68.20% हो गया है किंतु इन देशों की कीमतें काफी अधिक रही हैं। यह नोट किया जाता है कि इन आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती है।

(iv) मांग में कमी एवं अन्य कारक

प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध वस्तु का एकमात्र ऐसा बाजार है जहां पाटित आयात घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु से सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं। माँग में कमी घरेलू उद्योग की क्षति का एक कारक नहीं है। आयातित संबद्ध वस्तु तथ्यज्ञा घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु समान वस्तुएं हैं और इनका उपयोग समान अनुप्रयोग/अंतिम प्रयोगों में किया जाता है। इस प्रकार कीमत निर्धारण आयातित स्रोतों अथवा घरेलू स्रोतों से वस्तु की खरीद के निर्धारण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक बन जाता है।

(v) प्राधिकारी नोट करते हैं कि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देशों से फैंरो सिलिकॉन के आयातों में भारी वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों से निर्यात कीमत में कमी के परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु की पहुँच कीमत कम हुई है और पाटित आयात कीमतों की बराबरी करने के अपने प्रयास में घरेलू उद्योग क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य हुआ है और उद्योग अनेक स्रोतों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद प्रत्येक वर्ष हो रहे घाटे से उबरने में समर्थ नहीं हुआ है।

(vi) प्राधिकारी मांग में कमी, खपत की पद्धति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहारों तथा विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। यह भी नोट किया जाता है कि प्रौद्योगिकी में विकास घरेलू उद्योग की क्षति का कारण नहीं रहा है। इन मापदंडों से संचयी और सामूहिक रूप से यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

29. संबद्ध वस्तुओं के लिए पहुंचमूल्य का निर्धारण भारित औसत सी आई एफ निर्यात कीमत, सीमाशुल्क के उपयुक्त स्तर [धारा 3, 3(क), 8 ख, 9, 9(क) और उत्तराई प्रभार लिए 1% को छोड़कर] को जोड़ कर किया गया है।

30. घरेलू उद्योग के लिए समान वस्तुओं की क्षति रहित कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के दो प्रमुख उत्पादकों अर्थात् मै0 आर एम एफ ए,

भुवनेश्वर और मै0 वी बी सी फैरो एलॉएज, हैदराबाद की संबद्ध वस्तु की वास्तविक उत्पादन लागत का उपयोग किया है ताकि घरेलू उद्योग की ईष्टतम उत्पादन लागत का निर्धारण किया जा सके जिसमें मानकीकृत सर्वोत्तम खपत मानदंडों और ऐसी कच्ची सामग्री जिसकी जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु खपत की गई है, की वास्तविक कीमत को ध्यान में रखना होगा। प्राधिकारी ने मै0 हाई टेक इलेक्ट्रोथर्मिक्स और हाइड्रोपावर लि0 द्वारा प्रस्तुत लागत संबंधी सूचना को अपूर्ण तथा अपर्याप्त माना है और इसलिए उक्त फर्म द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की अनदेखी की है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु जांच अवधि के लिए निर्धारित कारखाना द्वार पर क्षति रहित कीमत की तुलना आयातित वस्तु की पहुंच कीमत के साथ की गई है।

पाटन मार्जिन तक शुल्क

31. प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन के समकक्ष या उससे कम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है जो यदि लगाया गया तो घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करेगा।

य. भारतीय उद्योग का हित

32. पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनःस्थिति लाना है जोकि देश के सामान्य हित में है।

प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किंतु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे। भारतीय उद्योग का ह्रास रूकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी।

प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

ट. निष्कर्ष

33. प्राधिकारी पूर्वोक्त पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि:

- (i) दक्षिण अफ्रीका एवं मैसिदोनिया से फैरो सिलिकॉन का निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है :
- (ii) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है:

- (iii) वास्तविक क्षति संचयी रूप से संबद्ध देशों/क्षेत्र से पाटित आयातों के कारण हुई है:
- (iv) प्राधिकारी संबद्ध देशों से फैंरो सिलिकॉन के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक समझते हैं ताकि घरेलू उद्योग की क्षति को दूर किया जा सके। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन उपरोक्त पैराग्राफों में दर्शाया गया है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम पाटन रोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने का प्रस्ताव करते हैं जिसे यदि लगाया जाता है तो उससे घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त हो जाएगी। क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना जांच अवधि के लिए निर्धारित घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत के साथ की गई है :
- (v) तदनुसार प्राधिकारी सिफारिश करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और मैसिदोनिया के मूल के या वहां से निर्यातित सीमा शुल्क शीर्ष 7202.21 के अंतर्गत आने वाले फैंरो सिलिकॉन के सभी आयातों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए। नीचे उल्लिखित क्षेत्रों/देशों के मूल के या वहां से निर्यातित सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 72 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क निम्नलिखित सारणी के कालम 3 में उल्लिखित राशि तथा प्रति मी.टन आयात के पहुंच मूल्य के बीच का अंतर होगा:-

सी.एन(1)	(2) निर्यातक/देश	(3) अम.डा./मी.टन
क	दक्षिण अफ्रीका: सभी निर्यातक/उत्पादक	728.44
ख	मैसिदोनिया: सभी निर्यातक/उत्पादक	728.44

- (vi) इस उद्देश्य के लिए आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 तथा 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमाशुल्क शामिल होंगे

34. उपर्युक्त के अध्याधीन प्राधिकारी दिनांक 11 जुलाई, 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

35. इस आदेश के विरुद्ध अपील पूर्वोक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद तथा स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

एल. बी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2003

FINAL FINDINGS

Subject :—Anti-dumping investigation concerning imports of Ferro Silicon originating in or exported from the South Africa and Macedonia

No. 14/8/2002-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof;

A. PROCEDURE:

2. The procedure described below has been followed:

(i) The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Indian Metals and Ferro Alloys Ltd, Bhubaneswar on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Ferro Silicon originating in and exported from South Africa and Macedonia (hereinafter referred to as subject countries / territories);

(ii) The Authority notified the Embassies of South Africa and Embassy of Macedonia in India (Through Embassy of India in Sofia, Bulgaria) about the receipt of fully documented petition made by the petitioner before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra;

(iii) The Authority issued a Public Notice dated 11th April 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping proceedings concerning imports of Ferro Silicon falling under Chapter heading 72 of Schedule I of the Customs Tariff Act.

(iv) The Authority sent questionnaires, to elicit relevant information, to the following known exporters from South Africa and Macedonia:

a). Macedonia

M/s. Jugochoram, 91215-Juguncvce, Republic of Macedonia

b). South Africa

M/s. Samancor Chrome, 6, Hollard Street, Johannesburg 2001

M/s. Nimag Limited, 37, Lincoln Street, Woodmead East, Gauteng, South Africa.

(v) The Embassies of South Africa and Macedonia were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) with a request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter, non-confidential petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to them, along with the name and addresses of the exporters.

(vi) A questionnaire was sent to the known importers of Ferro Silicon in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4).

(vii) The Designated Authority issued Preliminary Findings vide notification dated 11th July 2002 and forwarded a copy of the preliminary finding to the known exporters and industry associations and gave them an opportunity to make their views known in writing within 40 days from the date of the letter;

(viii) The Authority provided a copy of the preliminary findings to the Embassy of South Africa and Macedonia with a request that the exporters and other interested parties may be advised to furnish their views on the preliminary findings;

(ix) Additional information regarding injury was sought from the petitioner, which was also received;

(x) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file as per Rule 6(7) and kept it open for inspection by the interested parties. All parties who made request for inspection, in writing, were allowed to inspect the public file;

(xi) The Authority sought and verified information deemed necessary for the investigation, and the investigations were carried out at the premises of Petitioner's as well as other domestic industry.

(xii) The Authority also conducted cost investigation to work out optimum cost of production and cost to make and sell subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles based on the information furnished by the petitioner.

(xiii) The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 18.09.2002. All parties presenting views orally were requested to file written submissions, of the views expressed orally. The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals, if any.

(xiv) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties and comments received on the same have been addressed suitably in the final findings.

(xv) Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) on the information furnished by the petitioners so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

(xvi) **** In this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

(xvii) Investigations were carried out for the period 1st April 2001 to 31st December 2001.

Views of Petitioners, Exporters, Importers and Other Interested Parties:

B. Product under Consideration and Like Article

(a) Product under Consideration

3. The product under consideration is Ferro Silicon which is an alloy of iron and silicon containing calcium, aluminum, carbon, sulphur and phosphorous as impurities. Silicon constitutes the

major proportion in Ferro Silicon.(hereinafter referred to as subject goods). The size of Ferro Silicon is generally described in terms of millimeter of the outer dia of the product.

Ferro Silicon is primarily used as a deoxidiser in the production of steel and alloy steels. Ferro Silicon is also used in the manufacturing of power rectifiers and welding electrodes. The various users of Ferro Silicon can be described as under:

- Deoxidiser in the production of steel,
- As an alloying element for steel,
- In the making of electrical grade steel,
- In the production of anti-corrosive and acid resistant steel,
- In the manufacturing of power rectifiers,
- In the manufacturing of welding electrodes,
- It is added to cast iron as graphitising agent,

Ferro Silicon is classified under Customs sub-heading Nos. 7202.21 and 7202.2100 of Chapter 72 of the Customs Tariff Act, 1975. For the purpose of investigation, the Authority has taken Ferro silicon as the one containing by weight more than 55% of silicon. The Authority confirms the preliminary findings on Product under consideration.

(b) Like Article

Views of the Domestic Industry:

4. (i) There is no difference in the Ferro Silicon produced by Indian Industry and those exported from the subject countries, which can have an impact on price. The Ferro Silicon produced by the Indian industry and imported from the subject countries is comparable in terms of characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. Consumers of Ferro Silicon have used the two interchangeably. Therefore Ferro Silicon produced by the petitioner and those imported from the subject countries should be treated as like articles in accordance with Anti Dumping rules.

(ii) There is no known significant difference in the technology adopted by the Indian Industry and the manufacturers in the exporting countries. The technology employed throughout the world is the smelting process. The process adopted by the Indian industry is comparable with the technology adopted by the manufacturers of Ferro Silicon in the subject countries.

Examination by the Authority

5. (i) Rule 2(d) of the Anti-dumping Rule specifies that like articles mean an article, which is identical and alike in all respects to the product under investigation or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the articles under examination

(ii) Ferro Silicon is an alloy of iron and silicon containing calcium, aluminum, carbon, sulphur and phosphorous as impurities. There is however no significant difference in terms of process, equipment or technology for the production of Ferro Silicon. Ferro Silicon is primarily used as a deoxidiser in the production of steel and alloy steels. Ferro Silicon is also used in the manufacturing of power rectifiers and welding electrodes. In order to establish that Ferro Silicon produced by the domestic industry is a Like Article to that exported from subject countries, characteristics such as technical specifications, manufacturing process, functions and uses and tariff classification have been considered by the Authority. M/s TISCO has pointed out that there are some specialized grades like high and semi high purity Ferro Silicon which locals producers find it difficult to produce as they invest very less into the R&D and gain the expertise to compete within this niche. However no evidence has been adduced by them to indicate that imported Ferro silicon is not substituting the domestically produced Ferro silicon either technically or commercially.

(iii) The Authority finds that there is no substantiative argument disputing the fact that Ferro Silicon produced by the domestic industry has characteristics closely resembling the imported material and is substitutable by Ferro Silicon imported from the subject country both commercially and technically. In view of the above the Authority holds that Ferro silicon produced by the domestic industry and those being imported from the subject countries are like articles within the meaning of the rules.

C. Initiation, Standing and Domestic Industry:

- 6.(i) The petition has been filed by Indian Metals & Ferro Alloys Ltd (IMFA), Bhubaneswar on behalf of the domestic industry. The petitioners have claimed that they account for almost 47% of the total Indian production of the subject goods. M/s. Hitech Electro Thermics and Hydro Power Limited, New Delhi with a standing of 9.92% of the domestic production has supported the petition filed by the Petitioner. The Authority also notes that subsequent to the provisional findings, another domestic producer M/s VBC Ferro Alloys, Hyderabad with a production share of 15.6% have also expressed their support to the petitioner. As per 5(3) of the anti dumping rules, DA shall not initiate any investigations pursuant to the application made under sub rule (a) unless it determines on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product that the application has been made by or on behalf of the domestic industry provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than 25% of the total production of the like article by the domestic industry. It has also been explained in the sub rules that the application is deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry if it is supported by those domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing, either support for or opposition as the case may be to the application.
- (ii) The Authority has examined the contention made by the petitioner. As per the information given by Indian Ferro Alloys association, the petitioner represents 46.89% of the total Indian Production. The petitioner and the supporters account for 72% of the total Indian Production.
- (iii) Thus, the Authority holds that petitioners satisfy the criteria of standing to file the petition on behalf of the Domestic Industry in terms of Rule 5(3) (a) of the Rules supra, for the purpose of preliminary finding. The Authority also considers these petitioner companies as 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) supra.

D. Period of Investigation

7. The Authority has taken POI from 1st April 2001 – 31st December 2001 being the most recent period for the investigation when this case was initiated on 11th April 2002. This period was also taken because of the closing of the quarters and the feasibility of getting the complete data. The Authority confirms that nine months time is adequate and just for Anti Dumping Investigation since it also synchronizes with the three quarters for which the relevant data could be available.

E. De Minimus Limits

8. As regards ascertaining that the imports from the subject countries during the period of investigation (POI) are above de-minimus levels, the Authority has referred to the DGCI&S published data for the POI.

Country Name	Quantity (MT)	%Age share in imports
South Africa	552	3.92
Macedonia	1902.68	13.53

Thus, the Authority finds that the imports from the subject countries during the POI are above de-minimus levels.

9. Other Views: Views of Indian Ferro Alloys Producers Association (IFAPA)

(i) As regards to our views on Anti-Dumping Investigations into imports of Ferro-Silicon from South Africa and Macedonia into India, we would like to inform you that the Ferro Silicon Industry has been suffering for last few years due to heavy and cheap imports from countries like China, Russia, Ukraine and now from South Africa and Macedonia.

(ii) The total capacity available in the country is approximately 1,75,000 tonnes. We may mention here due to increase in imports from the above said countries the present production in India has

come down to less than 70,000 tonnes. Almost 50% of the units are closed and the present production is hardly about 40% of the total capacity.

(iii) Ferro Silicon producers like Visvesvaraya Iron & Steel Ltd. and Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. have closed down their operations, as they were unable to compete with low import prices. Producers like Nava Bharat Ferro Alloys Ltd. Ispat Alloys Ltd. and Anjaney Ferro Alloys Ltd. have stopped production of Ferro Silicon due to the reasons mentioned above. Another major producer M/s. VBC Ferro Alloys Ltd. has been closed from 1st April 2002.

(iv) This Association has, time and again, discussed with Government the problems faced by the Ferro Silicon producers and is very much concerned about the dumping of Ferro Silicon, which is flooding this country. Of late, imports from South Africa and Macedonia are of serious concern.

(v) Producers of Ferro Silicon are facing steep increase in cost of production in view of increase in power tariff and all other inputs, including logistics and labour costs. Cheap imports coming into the country have prevented Indian producers from effecting legitimate price increase.

(vi) This Association representing manufacturers of Ferro Alloys in the country, support that the Anti-Dumping Duty provisionally implemented vide Notification No.7/2002-Cus dated 13th August 2002, be finally determined on all imports of Ferro Silicon, originating in or exported from the above mentioned countries viz. South Africa and Macedonia, to enable Indian producers to regain viability.

Comments on Disclosure statement

9 A. The petitioner supports the disclosure statement with regard to product under consideration, like article and standing of the domestic industry.

F. Dumping Margin

10. Views of Importer M/s Tisco, Kolkatta

(i) We deeply regret that South African exporters have not given data to substantiate the domestic prices to arrive at the normal value. However, consideration of assured cost (constructed on the basis of figures provided by the petitioners) is not correct. A better alternative is provided under WTO, if we compare export prices from South Africa to other destinations, we find these are in fact same or even lower than that for India. The price at which South

Africa has exported Ferro Silicon to the USA, Japan and Europe during the Period of Investigation, is less than the 523/MT (average weighted CIF price of Rs.24859/MT at 1 US \$ = Rs.47.50 as mentioned in the preliminary findings). Thus, if we consider the price at which Ferro Silicon is exported from South Africa to third countries then it is established beyond doubt that, apart from minor variation on account of ocean freight etc. the export prices to India are comparable to that for third parties, and, therefore, there is no question of the said product being dumped India.

(ii) Normal value constructed on the realistic cost base of US \$ 336/MT, after adding incidence of ocean freight, inland freight, port expenses, selling and general expenses, and normal profit, is well below the export price of US \$ 523 per MT (CIF). Hence, the contention of the petitioners that South Africa is dumping Ferro Silicon into India by export at prices lower than the normal value does not hold true, and establishes without doubt that there is no dumping.

11. Views of the Domestic Industry

- a. As regards normal value determination from South Africa and Macedonia, efforts were made to obtain information with regard to the prices of the subject goods prevailing in the domestic market in the subject countries. The petitioner adds that they had not been able to get any authentic information in this regard. The petitioner tried to obtain the prices at which the exporters from South Africa and Macedonia are exporting the subject goods to other countries. However, no published information could be traced in this regard. Therefore, the petitioner has constructed normal value on the basis of standard consumption norms for the major raw materials and utilities. The petitioner has referred to the earlier cases where normal value has been determined on the basis of constructed value from the same subject countries
- b. As regards export price calculation, the petitioner has taken the information from DGCI&S with regard to actual volume imported and their prices from the subject countries during POI. The petitioner has calculated the ex factory export price after making adjustments. The petitioner has arrived at dumping margin for Macedonia and South Africa.
- c. The Designated Authority had earlier investigated dumping of the product by the exporters from Russia, Ukraine and China. The same resulted in imposition of anti dumping duties, which are now in force. With the imposition of anti dumping duties on these sources, the domestic industry has been able to increase its

production, capacity utilization and sales volumes. However, the producers in the subject countries have started dumping the subject goods, which has prevented the domestic industry from raising the prices to optimum level. The petitioner adds that injury to the domestic industry may be examined in the light of injury earlier suffered by the domestic industry.

- d. None of the exporters from Macedonia and South Africa have responded to the Designated Authority. The exporters have thus preferred non-cooperation in the present investigation. The Authority is therefore fully justified in proceeding with the best information available in accordance with the Indian Anti Dumping Rules.

11A. Comments by the Domestic Industry to the Disclosure Statement.

The petitioners supports the Disclosure Statement with regard to dumping. With regard to the argument of TISCO, the petitioner submits that TISCO as an importer cannot advance arguments on dumping determination. If the South African exporters consider it unnecessary to respond to the Designated Authority, TISCO cannot plead that there is no dumping, considering the price at which goods might have been exported from South Africa to other countries.

12. Examination by the Authority

Under Section 9A(1) (c) normal value in relation to an article means:

(i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6)";

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

(iii) The Authority notes that none of the exporters from South Africa and Macedonia has submitted any information regarding annexure attached with the exporters questionnaire. As no information about domestic sales price structure of the subject goods, its cost of production in South Africa and Macedonia and other information as per the questionnaire has been furnished, the Authority has proceeded to rely upon the best available information for determination of normal value. The petitioners have claimed normal value in respect of South Africa and Macedonia on the basis of constructed cost of production. The Authority finds that none of the exporters have given any information to enable it to determine the normal value based on the domestic sales price. The Authority confirms, in the absence of any response from the exporters from subject countries in the form and manner prescribed, having made the findings with regard to exports from subject countries on the basis of the facts available to it as per rule 6(8) supra.

(iv) Accordingly, the Authority has constructed the normal value on the basis of facts available with the applicable adjustments. The normal value so determined for South Africa and Macedonia is US\$****/MT and US\$****/MT respectively.

(v) Though the petitioner has submitted information regarding imports of subject goods from subject countries, the Authority has relied on the data received from DGCI&S for imports from subject countries. The Authority notes that the South Africa has exported 552 MT during the POI at a price of US\$ 288833.7. The weighted average CIF price as per the information available with the authority (DGCI&S) is determined at Rs 24859 /MT. The ex-factory export price has been determined after admitting US\$ ****/MT as ocean freight, **** % as marine insurance charges and US\$ ****/MT for port expenses and transportation charges (inland). Commission @ ****% for the Indian indenting agent has been disallowed by the authority for want of documentary evidence. After adjustments on

these accounts, the ex-factory FOB price is estimated at Rs***/MT or US\$ ***/MT at an average exchange rate of Rs 47.51 = 1US\$.

(vi) As regards determination of export price from Macedonia, the Authority notes that the Macedonia has exported 1902.68 MT during the POI at a price of US\$775389. The weighted average CIF price as per the information available with the authority (DGCI&S) is determined at US\$ 407.52/ MT. The ex-factory export price has been determined after admitting US\$ ****/MT as ocean freight, ****% as marine insurance charges and US\$***/MT for port expenses and transportation charges (Inland). Commission @ ***% for the Indian indenting agent has been disallowed by the authority for want of documentary evidence. After adjustments on these accounts, the ex-factory FOB price is estimated at Rs***/MT or US\$ ***/MT at an average exchange rate of Rs 47.51 = 1US\$.

(vii) The Dumping Margin for South Africa comes to US\$ **** or 39.38 % of export price and dumping margin for Macedonia comes to US\$**** or 95.48 % of export price.

Dumping Margins			
Countries/Exporters	Normal value	Export pr	D.M%
South Africa: All producers/Exporters	****	****	39.38
Macedonia: All Producers/Exporters	****	****	95.48

G. INJURY

13. Views of the Importer M/s TISCO

(i) The domestic producers not having access to cheaper source of captive power, are faced with the threat of injury not because of the fact that several countries, (Russia, Ukraine and China) and now South Africa and Macedonia are "Dumping" Ferro Silicon to India, but because of the fact that due to the very high cost of power in India (almost 5/6 times that of South Africa), the production of Ferro Silicon (which consumes over 9000 KWH per MT) is not at all competitive in global terms.

(ii) Further, the international prices of Ferro Silicon have been decreasing over the years, as a result of which, the Indian producers, already plagued with high cost of power, are no longer globally competitive, and are, therefore, faced with the threat of injury, even though Ferro Silicon is being imported (and not dumped) at the prevalent marked prices. Therefore, it stands established there is no Causal Link (As provided in Annexure-2 of the Anti-Dumping Rules), between the imports of Ferro Silicon

from the subject countries, and the injury to the domestic producers.

(iii) Therefore, if Anti-Dumping Duty is imposed on the subject countries, then the importers will have no choice but to explore alternative locations, till they run out of possible sources. This in effect, is the intention of the petitioner company, to ensure that more and more countries are covered under the gambit of ADD and the Indian market is isolated from the pressures of globalization. Thus, the petitioner company is aiming to create a protected market place, wherein it can continue to exploit the consumers and make huge profits.

14. Views of the Importer M/s Jindal Strips Ltd

1. It is observed from the application as well as the preliminary findings that the application has been filed by the petitioners who have claimed to represent the domestic industry. The petitioner's account for 46.89% of the production during the period of investigation while the supporter's account for 9.92% of the domestic production. It is respectfully submitted that while the petitioners may have the standing to file to application on behalf of the domestic industry, it does not follow that the petition has provided the requisite information for examination of various injury parameters like market share, prices and the causal link.
2. Without prejudice to the above, we wish to submit that the domestic industry has not suffered any injury on account of imports from the subject countries. The injury parameters do not show the existence of any injury. At the same time, there is hardly any factor indicating the existence of causal link, which is a prerequisite for imposition of even the provisional duties.
3. Injury parameters like sales, output and capacity utilization show an increase as compared to previous years and their inventories have also declined significantly during the POI since previous years. Besides there is no comment on the other injury parameters like employment, wages, cash flow, growth and ability to raise investments. Additionally, while the market share of the imports have been compared with total imports, no such comparison have been made with regards to changes in the share of domestic industry to total consumption over the years. As mentioned in the Directors report, their financial performance has got affected by adverse and depressed market conditions and situation of loss can be attributed to imports from subject countries. Further, the petitioner has not submitted any analysis of factors affecting domestic prices beyond saying that their prices are affected by imports.

4. The importer has voiced its concern that losses to the petitioner could be because of factors other than dumping. The petitioner's entire attempt has been to block the supplies from all sources so as to allow them to charge monopolistic prices. They have emphasized that an analysis of the injury data of the petitioner establishes a complete absence of causal link.

14A. Comments to the Disclosures by M/s. Jindal Strips Limited.

I. All the parameters of Injury pertaining to the domestic industry has shown improvement over the preceding period and it is unconceivable that any injury has been caused to the domestic industry. As regards the losses, it may be appreciated that the domestic industry was incurring losses even prior to the alleged dumping and their position has only improved during the period of investigation. In this connection, it is only also submitted that price under-selling which has been considered as a prime and only factor of injury, is in fact, not a factor of injury as envisaged under annexure II of the Anti-Dumping Rules. It is respectfully submitted that it would not be permissible to make an inference of injury on the ground of its inability to realize the NIP.

II. The price under-cutting analysis proposed to be done by the Designated Authority appears to be defective as the price under-cutting is required to be done country-wise. There is also complete absence of causal link between the alleged dumped imports and the alleged but non-existent injury to the domestic industry.

III. As regards market share, the domestic industry has been able to improve its market share and this cannot be a possible cause of injury to the domestic industry.

15. Views of the Domestic Industry

1. The petitioner has represented that imports of Ferro silicon have increased substantially from the subject countries in absolute terms as well as in relation to the imports of subject goods in India, and in relation to the production of the domestic industry and also in relation to the demand of the subject goods in India. They have cited significant decline in the export price from subject countries which are below the selling price of the domestic industry and which has resulted in price undercutting. The export price is below the cost of the production of the domestic industry and also below the non-injurious price of the

domestic industry and below the landed price of imports from all countries attracting Anti Dumping duties.

2. The petitioner adds that increase in the production of the domestic industry and capacity utilization has to be seen along with selling price and cost of production of the domestic industry, efforts of the domestic industry to produce more to reduce fixed overheads and imposition of Anti dumping on a number of countries. The domestic industry has been forced to suffer losses in spite of significant improvement in production. Similarly increased sales volume must be seen in the context of imposition of anti dumping duties on a number of countries. They add that the domestic industry has not been able to raise the prices to the expected levels in spite of increase of production and sales of subject goods. They add that the domestic industry continues to suffer financial losses in spite of imposition of anti dumping duty on a number of sources. Some parameters like production, capacity utilization, sales, stocks and losses per unit do show improvement due to reason that improvement of these parameters was due to the imposition of anti dumping duty on a number of sources.
3. As regards the arguments of the Jindals that losses of the petitioner industry have gone down by 58% over last year when actually import prices have gone down over the last year, the petitioner represents that fallacy in the table given by Jindal is established by the reworked out table given below.

Year	Import from Macedonia			Import from South Africa			Total Imports		
	Q,MT	Value	Rate .	Q,MT	Value	Rate Rs.	Qty MT	Value	Rate
		Rs.Lac	Rs/MT		Rs.Lacs	/MT		Rs.Lac	Rs/MT
1999-0				20	4.03	20150	20	4.03	20150
2000-01	54	11.86	21963	54.6	28.52	52234	108.6	40.38	37182
POI	1902.7	371.91	19546	552	137.22	24859	2454.7	509.13	20741

4. It would be seen that the table shows ferro silicon having been imported at a rate of Rs.52.23 per kg. Would Jindal argue that ferro silicon has been imported into India (and Jindal would buy the material) at an average CIF price of Rs.52.23 free of customs duties! Jindal has simply ignored the possible error in the data.

5. Fallacy in the table and argument put by Jindal is further established once the information with regard to other countries is also examined. Information with regard to imports from various countries was earlier provided by the petitioner. It would be seen that the dumped imports at much lower prices were available from various countries (which are now attracting duties). Thus, it would not be appropriate to argue that import price from South Africa declined from Rs.52 to Rs.25 whereas the losses of the domestic industry also declined. Losses to the domestic industry in the previous year were due to dumped imports from other countries.

6 ROI for the domestic industry continues to be negative and in spite of the improvement of productivity, the domestic industry has suffered financial losses due to sub optimal prices prevailing in the market due to dumping. The company has option but to increase the wages of the employees given statutory regulations. Considering the present situation, the domestic industry cannot think to raise further capital issue for expansion and investment.

Comments of the Domestic Industry to the Disclosure.

15A. With regard to improvement in a number of injury parameters, argument of M/s. Jindal Strips Limited lacks appreciation of the market situation. It has been conveniently ignored by Jindal that the earlier period with which Jindal has drawn comparison and conclusion itself was a period of injury to the domestic industry from dumped imports. We have provided a decision of EC in the matter of Ferro Silicon Manganese from China PR (Counsel Reference NO. 495/98 dated 23rd February 1998) wherein it has been clearly held that it has to be kept in mind while evaluating injury to the domestic industry that the industry was recovering from earlier dumping of the product in the market.

EXAMINATION BY AUTHORITY

16. Analysis of injury to the domestic industry has been done on the basis of the information available on record and the verification done by the officials of the Director general of Anti Dumping and Allied Duties. As regards the observation made by certain importer, the Authority has determined the injury information with respect to M/s IMFA, Bhubaneshwar and M/s VBC Ferro Alloys, Hyderabad, which now

constitute 62% of the domestic industry. In order to fully assess the evolution of the various injury parameters, the fact may be borne in mind that the domestic Industry was confronted with a growing Ferro Silicon demand, which had to be met in terms of production and Anti Dumping duty is presently in force against imports originating in or exported from Russia, China PR and Ukraine. The particular impact of these types of measures has been taken into consideration while analyzing various injury factors for the time period after 1998-99. The following parameters have been analyzed for the purpose of assessment of injury to the domestic industry.

Volume and Market Share of Dumped Imports

17. The Authority has examined the information regarding the volume of exports from the subject countries during the period of investigation and the preceding years. During the POI the imports from the two subject countries taken together were 2454 Mt and 3272MT(Annualized). During the year 2000-2001 these imports were 108 MT (as per DGCI&S data). These imports from the subject countries accounted for a market share of 0.1% in 1999-2000, 0.61% during 2000-01 and 17.47% during POI. When compared to the previous year 2000-01 the share in the market had shown a quantum increase during the POI. The Authority notes that the market share of the domestic industry have gone down during the Period of Investigation as compared to previous years. Though the market share improved from 1999-00 to 2000-01, namely, after the imposition of definitive measures against imports originated in Russian, Ukraine and China PR, it has, however, been noted that this increase has not allowed the domestic industry to regain the position it had before the injurious dumping from the subject countries.

Increase in Imports					
	Unit	98-99	99-00	00-01	POI Annl
Macedonia	MT	0	0	54	2537
South Africa	MT	100	20	55	736
Subject countries	MT	100	20	109	3273
Countries with AD	MT	2615	9857	6617	2686
Others	MT	1660	10847	11196	12779
Total	MT	4375	20719	17921	18738

Market share in Imports					
	Unit	98-99	99-00	00-01	POI Annl
Subject countries	%	2.29	0.1	0.61	17.47
Countries with AD	%	59.78	47.58	36.92	14.34
Others	%	37.94	52.33	62.47	68.2
Total	%	100	100	100	100

Market share in Demand					
	Unit	98-99	99-00	00-01	POI Annl
Subject countries	%	0.16	0.03	0.13	3.64
Countries with AD	%	4.24	12.8	7.76	2.98
Others	%	2.69	14.08	13.13	14.2
Domestic Industry	%	45.58	37.86	42.36	41.68
Indian Industry	%	92.9	73.09	78.98	79.17

Production and Capacity utilization

18. The Authority notes that the production of the domestic industry has increased over the years. With capacity of domestic industry remaining same, higher production has led to higher capacity utilization for the domestic industry. Nevertheless, even this increase of rate of capacity utilization remains at a sub optimal level in view of increase in demand of the subject goods and imposition of anti dumping duties from other sources.

Sales Volumes

19. The Authority notes from the information available that sales volume of the company has increased over the years. The Authority notes that increase in sales volumes has to be seen in the light of the fact that consumption of the subject goods has increased. The domestic industry has, therefore, derived some advantage from this positive market situation. Profitability, however, still remains in a negative situation. It is, further noted that with increased sales, the domestic industry has been suffering financial losses as they have not been able to raise the price up to a level which would have permitted even recovery of full cost of production.

Price Undercutting and Price Underselling

20. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry, the principle (iv) of Annexure-II of the Anti-Dumping Rules states:

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic Industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

Price Undercutting from Subject countries

In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree. The Authority has compared the landed value of imports of subject goods from subject countries during the POI with the net sales realization and has found that there has been a price under-cutting by the dumped imports cumulatively from the subject countries. The landed value of imports has been found to be lower than the domestic industry's net sales realization.

Price Underselling from Subject countries

21. The Authority has also examined the claim of the domestic industry that the domestic industry is suffering injury on account of financial losses. The Authority notes that price underselling is an important indicator to make an assessment of injury. The Authority has worked out a fair selling price and compared the same to the landed value to arrive at the extent of price underselling. The Authority notes that the imports were having significantly suppressing/ depressing effect on the prices in the domestic market, as the domestic industry has not been able to raise its selling price to non-injurious level in view of the dumped imports from both the subject countries. The Authority thus concludes that the selling price of the domestic industry is significantly below the

price, which would have permitted the domestic industry, a fair recovery of its cost of production and earn a reasonable return.

Injury parameters					
		98-99	99-00	00-01	POI Annl
Parameters	Units				
Capacity*	MT	60,000	60,000	60,000	60,000
IMFA	MT	45000	45000	45000	45000
VBC	MT	15000	15000	15000	15000
Production*	MT	32792	37796	40829	45704
IMFA	MT	22319	26731	30763	33391
VBC	MT	10473	11065	10066	12313
Capacity Utilistion*	%	54.65	62.99	68.05	76.17
Sales*	Index	100	103.77	128.58	133.43
Opening Stocks*	Index	100	44.89	64.75	28.43
Closing stocks*	Index	100	144.26	63.33	42.52
Cost of production*	Index	100	96.1	96.76	95.19
Net sales realisation*	Index	100	97.34	95.39	96.77
Profit*	Index	100	73.44	121.71	66.45
Profit for product*	Index	-100	-74.31	-140.437	-101.934
Salary & Wages	Index	100	103	122	126
Cash Profit	Index	-100	-55.3	-170	-78.82
Return on capital*	Index	-100	-59.18	-124.9	-92.94
Employment*	Index	100	101.97	98.09	94.10
Productivity*	Index	100	113.04	126.93	148.12
Growth in sales*	%		3.77	23.9	3.77

* M/s IMFA, Bhubaneshwar and M/s VBC Ferro Alloys, Hyderabad

Thus, the dumped imports have prevented the domestic industry from effecting legitimate price increase to realize a reasonable price. The industry has suffered material injury on account of depressed selling prices resulting in non-recovery of cost of production and thereby suffering financial losses. The selling price of the domestic industry marginally increased during the POI as compared to year 2000-01. However, the same has been below the non-injurious price (NIP) on account of dumped imports.

Employment and Wages

22. The Authority notes that there is no significant change in the employment level of the domestic industry. The wages/salary have increased over the years

Inventories

23. The inventories have declined over the periods. Here the Authority notes that period being compared with the POI is a period of dumping faced by the industry with changed sources.

ROI and Cash profit

24. The domestic industry has been suffering a negative cash profit for the past 4 years and its cash flow position remains adverse.

Growth, Return on Capital and Ability to raise capital

25. The company has been able to register a growth rate of 3.7% during the POI over the previous years. It is also noted that capital employed has increased over the years due to higher utilization of facilities for production and sale of the product concerned. However, in spite of increase in capital employed, the domestic industry has suffered losses during the POI and earlier years. It is also noted that return on the capital employed has not further deteriorated and the same has shown marginal improvement. However, this may be seen along with the fact that the capital employed itself has significantly increased. The Authority concludes that cash flow, ROI and profitability of the domestic industry – all remains negative, which would adversely affect the ability of the domestic industry to raise fresh capital.

Closure of Other Units.

26. It is claimed by M/s IFAPA that a number of companies have one after another suspended production of subject goods due to continued dumping of the material in the Indian market. It is also noted that a significant number of the units have closed down their production due to dumping from the subject countries. It is also noted that another domestic producer M/s. Hi tech Electrothermics & Hydropower Limited is also incurring substantial losses on account of the production of the subject goods as reported in the balance sheet. Though the Authority has discarded the costing information of the said firm because of the incomplete and insufficient data, it is noted that the said company is incurring significant losses.

27. In brief, it can be concluded that

1. Imports of subject goods from subject countries have increased significantly in absolute terms. These imports have also increased in relation to total imports of subject goods in India.
2. Imports from the subject country have increased in relation to the production of the domestic industry and also in relation to the demand of subject goods in India.
3. Export prices have declined significantly and Imports from subject countries are undercutting the prices of the domestic industry.
4. The petitioner is suffering from price underselling also as landed price of subject goods are below the Non Injurious price or fair selling price of the domestic industry.
5. Dumped imports are preventing the domestic industry from effecting price increase up to a level of Non Injurious price. The profitability of the domestic industry remains sub optimal in view of the continued dumping from a large

number of sources. The petitioner is suffering from price suppression/depression, as weighted average landed price of the subject goods from subject country are less than cost of production of the domestic industry.

6. In view of the aforesaid observations, the Authority notes that various parameters listed above clearly indicate that imports have increased in absolute terms and also in relation to production of the domestic industry and in relation to the demand in India. With the decline in the export price from subject countries, imports are cumulatively undercutting the prices of the domestic industry and are preventing it to effect legitimate price increase to the level of Non injurious Price determined by the Authority. Imports are resulting in price underselling by the domestic industry and profitability of the domestic industry has remained sub optimal in spite of imposition of anti dumping duty on a number of sources.
6. Regarding observation made by the user industry that domestic industry is having their own source of power and hence any further benefit in the form of anti dumping duty is uncalled for, the Authority, after going through the records kept by IMFA, notes that the petitioner is getting power from its sister concern at a much cheaper rate than the tariff normally charged by State Electricity Boards. However even after getting power at a cheaper cost, the domestic industry has not been able to recover its cost of production.

H Cumulative Assessment of Injury

- 27A As per annexure-II (iii), in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to Anti-dumping investigation, the Authority is required to cumulatively assess effect of such imports, only when it determines that (a) the margin of dumping established in relation to imports from each country is more than 2% expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is 3% of the imports of like article --- and (b) cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic article. The Authority has found that the margin of dumping in respect of each of the subject country is more than 2% and the volume of imports from each country is also more than 3%. The Authority has also found it appropriate to cumulatively assess the effect of imports of the subject goods on the domestically produced like article and has found that there is a cumulative effect of injury by imports of subject goods on the domestic industry.

The above economic parameters cumulatively and collectively establish that domestic industry has suffered material injury on account of dumping.

Examination by the Authority on Causal Link

28. Annexure-2 (v) of Anti-Dumping rules states that it must be demonstrated that dumped imports are, through the effects of dumping as set forth in Para 2 and 4 of said annexure above, causing injury to the domestic industry. The demonstration of a causal relationship between the dumped imports and the injury to the domestic industry shall be based on an examination of relevant evidence before the designated authority. The

designated authority shall also examine any known factors other than the dumped imports, which at the same time are injuring the domestic industry, and the injury caused by these factors must not be attributed to dumped imports. Factors which maybe relevant in this respect include inter- alia, the volume and price of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

In order to reach its conclusions on the cause of the injury suffered by the domestic industry and in accordance with rule V of the Annexure II of the Anti Dumping Rules, the Authority examined the impact of all known factors and their consequences on situation in that industry. Known factors others than the dumped imports, which could, at the same time, have injured the domestic industry, were also examined to ensure that the possible injury caused by these other factors was not attributive to the dumped imports.

(i) Effect of the dumped imports

Between 1998-99 and POI, dumped imports from the subject countries as a proportion to total imports increased significantly in volume (57.44% to 98.34%) and from 0.16% in 1999-99 to 3.64% in the POI to the to total share in demand. As regards the export prices, they decreased during the whole period and undercut the domestic industry prices during POI on average by ****% (from subject countries). Moreover, undercutting figures did not show the full impact of the dumped imports, since domestic industry prices were depressed. Price of the dumped imports was below those of the domestic industry throughout the POI and exerted a pressure on them, which forced the domestic industry to decrease prices. It is, therefore, considered that the dumped imports caused material injury to the domestic industry.

(ii) Other factors: Performance of other producers: It has been claimed by interested parties that a number of industries manufacturing Ferro silicon have closed down due to dumping of the subject goods. The Authority notes that some of these industries had been closed prior to the POI and continued dumping from a number of sources could be one of the reasons for the closure of these units.

(iii) Imports from Non Subject countries

The Authority has analyzed the volume and price of the imports from Non subject countries from 98-99 and POI and notes that market share of non subject countries (other than subject countries and countries attracting duty) have risen from 37.94% in 98-99 to 68.20% during the POI but the prices from these countries have been much higher. It is noted that these imports could not have caused injury to the domestic industry.

(iv) Contraction of demand and other factors

The Authority observes that there is a single market for the subject goods where dumped imports compete directly with the goods produced by the

domestic industry. Decline in demand is not a factor causing injury to the domestic industry. The imported subject article and the domestically produced goods are like articles and are used for the same applications/end uses. Thus, pricing becomes the most important factor determining purchase of the article from either imported sources or domestic sources.

(v) The Authority notes that imports of Ferro Silicon from the subject countries increased tremendously during the POI as compared to previous years. The reduction in the export price from the subject countries resulted in low landed price of the subject goods and the domestic industry in its attempts to match the dumped import prices was forced to sell below its Non injurious price and the domestic industry has not been able to recover from the losses it is incurring every year despite imposition of anti dumping duty on a number of sources.

(vi) The Authority could not find any evidence of contraction of demand, change in pattern of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers. It is also noted that developments in technology has not been a cause for injury to the domestic industry. These parameters collectively and cumulatively indicate that the petitioner has suffered material injury due to the dumped imports.

29. The landed value has been determined for the subject goods after adding onto the weighted average c.i.f. export price, the applicable level of customs duties (except duties levied under Section 3, 3(A), 8B, 9, 9(A) and 1% towards landing charges.

30. While determining the non-injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual cost of production of the subject goods of two major producers of the subject goods i.e. M/s. IMFA, Bhubaneswar and M/s VBC Ferro Alloys, Hyderabad to determine optimum cost of production for the domestic industry which would take into account the normated best consumption norms and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation. The Authority has considered the costing information submitted by M/s. Hi Tech Electrothermics and Hydropower Limited, as incomplete and insufficient and has, therefore, discarded the data submitted by the said firm. For calculation of injury margin, the ex-factory non-injurious price determined for the period of investigations has been compared with the landed value of the imported goods.

Duty up to dumping margin:

31. The Authority recommends the amount of anti-dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST:

32. The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods.

The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from South Africa and Macedonia in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

K. CONCLUSIONS:

33. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

(i) Ferro Silicon has been exported to India from South Africa and Macedonia below its normal value;

(ii). The Domestic industry has suffered material injury.

(iii) The material injury has been caused cumulatively by the dumped imports from subject Countries/territory.

(iv). The Authority considers it necessary to impose definitive anti dumping duty on all imports of Ferro Silicon from subject countries in order to remove the injury to the domestic industry. The margin of dumping determined by the Authority is indicated in the paragraphs above. The Authority proposes to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry. For the purpose of determining injury, the landed value of imports is compared with the Non Injurious Price of the domestic industry determined for the period of investigation.

(v). Accordingly, the Authority recommends that the definitive Anti dumping duties be imposed by the Central Government on all imports of Ferro Silicon falling under Custom Heading 7202.21 originating in or exported from South Africa and Macedonia. The Anti-Dumping duty shall be the difference between the amount mentioned in column 3 of the following table and the landed value of imports per MT on all the imports of subject goods falling under Chapter 72 of the Customs Tariff, originating in or exported from the subject territory/countries mentioned below: -

C.N (1)	(2) Country/Exporter	(3) US\$/MT
A	South Africa: All Producers/Exporters	728.44
B	Macedonia: All Producers/Exporters	728.44

vi). Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.

34. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 11th July 2002.

35.. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal in accordance with the Act, supra.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority